being fulfilled by the Gas Authority of India Ltd. Even the registered parties are not getting the allocations. Will the Minister look into it and see that at least the parties who have been allocated, will get the gas and also those who registered themselves, will get allocation soon?

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Krishna-Godavari basin produces at present about 3.4 million CMT of gas per day. This gas has been fully allocated. There are large numbers of applications pending. We have a programme of development of the Krishna-Godavari basin for which we have given the highest priority. As and when additional gas is produced, those who are in the priority category for gas allocation, will be considered.

MR. CHAIRMAN: Next question.

दिल्ली परिवहन निगम का घाटा

***223. डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :†**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली बसों के किराये को बढ़ाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निगम को हो रहे निरन्तर घाटे को पूरा करने के लिए अधिक किराये वाली नई बस सेवाएं भी चलाई गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन सभी उपायों के बावजूद निगम का घाटा कम नहीं हो रहा है ;

(घ) क्या सरकार निगम के घाटे के कारणों की पुन: जांच किये जाने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं तथा 1991–92 वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को कितना घाटा हुआ है ?

†सभा में यह प्रश्न डा० जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा पूछा गया ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) and (e) A Group of Ministers has been set up by the Government under the Chairmanship of Minister of Finance to work out an inter-connected package for the rehabilitation of Delhi Transport Corporation. The provisional operating loss of D.T.C. during the year 1991-92 is estimated at Rs. 83.25 crores.

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : सभापति जी मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वीकारा है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किराये बढ़ाए जाने के बावजूद और अधिक किराए वाली बसें चलाए जाने के बावजद निगम बहुत भारी घाटे में है । मंत्री जी का अनुमान है कि वार्षिक घाटा 83 करोड रुपए का है, लेकिन मेरी सूचना है कि वार्षिक घाटा 197 करोड़ रुपए का है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बसों के इस बीमार बेड़े के अतिरिक्त दिल्ली की जनता की परिवहन की समस्या को सुलझाने के लिए आपकी और क्या-क्या योजनायें हैं–मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम या अडरग्राउन्ड रेलवेज या यमुना नदी में नावें चलना या और कोई योजना ? आखिर किस प्रकार आप दिल्ली की जनता की परिवहन की समस्या को सुलझाने का विचार रखते हैं ?

SHRI JAGDISH TYTLER: I would like to inform the hon. Member that the cash losses in 1990-91 were of the order of Rs. 113 crores, and this has been brought down to Rs. 83 crores in 1991-92. I hope by the end of 1992, the cash losses will be brought down

to Rs. 30 crores. That is how I am working out.

About the second part of the question, we have already allowed the Delhi Administration to freely give permits to the private people and I am glad to say that permission has been given for 3000 premits to be given in Delhi. Delhi Administration is on the final stages of this work and I think within this week or next week, they are going in for open lottery, and once these three thousand buses come on the road, the problem will be eased to some extent. The whole of Delhi has been divided into five zones. According to the requirements, these 3,000 buses have been set apart for the whole of Delhi. I am very hopeful that once these permits are released and the buses are on the road, Delhi people will get some relief.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: What about plying boats on the Yamuna?

SHRI JAGDISH TYTLER: This does not come under my Ministry.

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : सभापति, जी, दिल्ली परिवहन मुख्यतः दो प्रकार का है । एक प्रकार है—आलीशान सड़कें, आलीशान कारें आदि-आदि । यह जो पहला प्रकार है वह शासक वर्ग के लिए है । दूसरा प्रकार है—टूटी हुई सड़कें, बिगडी हुई बसें । यह जनता के लिए है ।

श्री सभापति : प्रश्न जल्दी कर लो तो अच्छा रहेगा ।

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे जमुना पार में बस रही गरीब जनता की परिवहन आवश्यकता से वाकिफ हैं ? क्या वह जानते हैं कि पिछले दिनों से निजामुद्दीन का पुल टूटा हुआ है उस पर डी०टी०सी० की बसेज नहीं चल पा रही हैं । कालन्दी कालोनी का पुल थोडी सी सड़क के बनने के अभाव में अभी भी चालू नहीं हुआ है और इन पुलों के चालू न रहने से ... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : कितने सवाल करेंगे ?

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : : प्रश्न एक ही है । वहां इन बसों के चालू न होने से पुलों को टीक व्यवस्था न होने से डी.टी.सी. पर कितना आर्थिक फाइनेंसियल और आपरेशनल बर्डन बढ़ रहा है ?

SHRI JAGDISH TYTLER: I am well aware of the problems of the people of Yamuna *par* because I am from Delhi.

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो पुल दिल्ली के अंदर हैं वह दिल्ली प्रशासन बनाता है, उन्हें पैसा हमारी मिनिस्ट्री से जाता है । अभी पुलों के अंदर जो कमियां पायी गयी हैं वह मैन स्टक्चर के अंदर नहीं पाई गई हैं । सड़क के अंदर जो पानी की पाइप डाली हुई थी उसकी लीकेज के कारण है । परन्तु उसकी भी रिपेयर हो रही है और हमारे फ्यूचर प्लान के अंदर भी जमना के ऊपर और दो-तीन पुल देने का विचार है और जिसे हम सैक्शन कर रहे हैं ।

श्री रणजीत सिंह : माननीय सभापति जी जैसा अभी आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि बसेंज के जो ईयरली घाटे हैं वह इस कारण हैं । मैं समझता हूं कि डी०टी०सी० की बसेज के घाटे के बारे में जब से हम हाउस में सुन रहे हैं वह तब से लगातार घाटे ही घाटे में जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बस एक ही होती है क्योंकि जब उसे प्राइवेट आदमी ले जाता है जिसकी चेसिस वही है बॉडी बिल्डर्स भी सेम ही है । वह आदमी पैसा भी कमाते हैं इस्टॉलमेंट भी रि-पे करते हैं और बच्चों को भी पालते हैं और अगली बस का भी इंतजाम कर लेते हैं । डी०टी०सी० की बसेज हमेंशा घाटे में क्यों जा रही है, जबकि वही चेसिस हैं, वही बॉडी बिल्डर्स हैं । हर वर्ष जो घाटा बढ़ा है वह मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं सर ।

श्री सभापति : अब प्रश्न कर लो अच्छा रहेगा ।

श्री रणजीत सिंह : 1989–90 में ग्यारह हजार नौ सौ चौरासी लाख था 1990–91 में उन्नीस हजार सात सौ अड़तालीस है । 1991–92 का अभी जैसा आपने बताया है । तीनों ही साल में यह करोड़ों रुपए के घाटे में है । मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाह रहा हूँ कि डी.टी.सी. की चलने वाली बसेज चार हजार हैं और उसका जो कैलकुलेट करके निकालें... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : प्रश्न करलो ।

श्री रणजीत सिंह : मैं बता रहा हूँ सर, एक बस सत्ताइस हजार पांच सौ रुपया मुनाफा दे रही है । जब सत्ताइस हजार पांच सौ रुपया प्रति बस मुनाफा रहे तो फिर घाटे का कारण क्या है ? घाटा क्यों हो रहा है, किस कारण से उसका ब्रेकअप कोई बता ही नहीं रहा है ।

SHRI JAGDISH TYTLER: The main factors which are responsible for the losses of DTC are: Sharp increase in the prices of inputs since 1986. Steep increase in labour and establishment costs from January, 1986. Concessions to students and other weaker sections, which amount to Rs. 22 crores per annum. Large percentage of overaged buses, i.e. 33.85 per cent, which is the highest in the world. Staff in excess of the prescribed norms and requirements. Reinduction, in 1990, of over 3,000 staff. They are now idle. They should not have been taken.

Over and above this, in the case of DTC, we have to change the driver every eight hours. We have to change the conductor. A bus which is on the road requires three drivers and six conductors, sometimes. Whereas, a private person does not have to pay any hiring charges. He can employ just one driver and, perhaps, by paying him another Rs. 200, make him work beyond eight hours or twelve hours. That is how he is able to make more money.

MR. CHAIRMAN: Shri Prakash Ambedkar. He is not here. Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Environment Tar

*224. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI V. NARAYANASAMY:
Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state·

(a) whether Government have proposed the imposition of Environment Tax on developed countries to pay for the global environmental clean-up at the Ministerial Conference of developing countries on environment and development held at Kuala Lumpur recently;

(b) if so, the details of the proposals and the response of the participating countries thereto; and

(c) what was the outcome of the Kuala Lumpur Conference?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Ministerial Conference of Developing countries held at Kuala Lumpur on 26-29 April, 1992 issued a Declaration, copies of which have been placed in the Parliament Library for the kind perusal of Hon'ble Members.

Allocation for Major Ports

*225. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what are the details of the plan allocation made for development of different major ports during the 8th Five Year Plan period; and

(b) whether the present plan allocations to different Major ports would meet the requirements of port developments in view of existing capacity utilisation of different ports?